

## रेपो रेट अपरविरतति

### प्रीलिम्स के लिये:

रेपो दर, RBI

### मेन्स के लिये:

मौद्रिक नीति से संबंधित मुद्दे और उसका प्रभाव

## चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये अपनी छठी और अंतिम द्विमासिक नीति समीक्षा बैठक में [रेपो दर](#) (Repo Rate) को 5.15% पर ही बनाए रखने का नरिणय लिया है।

## प्रमुख बटु

- RBI ने चलनधिसमायोजन सुवधि (LAF) के तहत नीतगित [रेपो दर](#) को 5.15 परतशित पर अपरविरतति रखा है। परणामस्वरूप, LAF के तहत परतविरती रेपो दर 4.90 परतशित और सीमांत स्थायी सुवधि (MSF) दर तथा बैंक दर 5.40 परतशित पर अपरविरतति रखी है।
- MPC ने यह भी नरिणय लिया कि (यह सुनशिचति करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर है), जब तक वृद्धिको पुनरजीवति करना आवश्यक है, नभिवकारी रुख बरकरार रखा जाए।
- RBI ने नीतगित दरों और अपने रुख को यथावत रखा है लेकिन बैंकों के लिये फंड की लागत कम करने हेतु गैर-परंपरागत उपायों का सहारा लिया। इससे बैंक अपनी उधारी दरों में और कटौती कर सकेंगे, साथ ही उन्हें खपत मांग को पटरी पर लाने के लिये खुदरा उधारी को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।
- RBI ने बैंक से स्पष्ट कथिा कि भवषिय में ज़रूरत पडने पर दरों में कटौती की जाएगी। अभी मुद्रास्फीति की दर 7.4 फीसदी है और ऐसी स्थिति में दरों में कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है।
- RBI ने बैंकों से स्पष्ट कहा है कि यदि वे वाहन, आवास और SME कर्षत्रों को ऋण देते हैं तो उनके जमा आधार में से उतनी रकम कम हो सकती है जिससे उन्हें नरिधारति 4 फीसदी नकद आरक्षति अनुपात (CRR) में राहत मिल सकती है।
- RBI ने बैंकगि व्यवस्था में नकदी झोंकने और नकिलने के तरीकों में भी बदलाव कथिा है। हालाँकि उसने स्पष्ट कथिा है कि यदि ज़रूरत पड़ी तो वह परंपरागत तरीके अपनाने से नहीं हचिकेगा। नई व्यवस्था के तहत RBI ने दीर्घकालिक रेपो परचालन शुरू कथिा है। ये दो तरह की नकदी परतभूतथिों होंगी जनिहें बैंक मौजूदा रेपो दर पर एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि के लिये पैसा उधार लेने हेतु इस्तेमाल कर सकेंगे। हालाँकि इसका इस्तेमाल केवल एक लाख करोड़ रुपए तक के उधार लेने में ही कथिा जा सकता है।

## वशिलेषणात्मक रूप से इसका प्रभाव

- RBI का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष की तीसरी तमिाही तक मुद्रास्फीति घटकर 3.2 फीसदी हो जाएगी। हालाँकि अभी काफी अनरिचतिता बनी हुई है। यदि मुद्रास्फीति में RBI के अनुमान के अनुसार कमी आती है तो वह नीतगित दरों में 25 आधार अंक की कमी कर सकता है। इस स्थिति में रेपो दर 4.9 फीसदी हो जाएगी।
- मौद्रिक नीति के माध्यम से इससे अधिक सहयोग हेतु वृद्धि करना मुश्किल होगा। यदि अनुमान से अधिक अवस्फीति होती है तो कुछ संभावना बन सकती है। ऐसा कोरोनावायरस के कारण वैश्विक वृद्धि में धीमापन आने से हो सकता है।
- केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 6 फीसदी की दर से बढ़ेगी। चूँकि भवषिय में मौद्रिक राहत की गुंजाइश सीमिति है इसलिये केंद्रीय बैंक अब परेषण और ऋण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रति कर रहा है।
  - उदाहरण के लिये उसने वाहन, आवास और सूक्ष्म, लघु और मझोले उपकर्मों (MSME) को ऋण देने के मामले में बैंकों को 30 जुलाई, 2020 तक नकद आरक्षति अनुपात बरकरार रखने के मामले में राहत दी है।
- RBI ने अधिसूचति वाणज्यिक बैंकों द्वारा मझोले उपकर्मों को दथि जाने ऋण का बाह्य मानकीकरण करने का भी नरिणय लिया है। यह अगले वित्त

वर्ष के आरंभ में शुरू किया जाएगा।

- इन हस्तक्षेपों के अलावा RBI एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि के लिये दीर्घावधि की रेपो दर की व्यवस्था भी करेगा। करीब एक लाख करोड़ रुपए की इस राशि से बैंकिंग तंत्र में अधिक पैसा आएगा और ऋण दरों में कमी आएगी। लंबी अवधि के बॉण्ड और बैंक ऋण दर के मामलों में मौद्रिक पारेषण धीमा रहा है।
  - उदाहरण के लिये 10 वर्ष के सरकारी बॉण्ड के मामले में प्रतफल 76 आधार अंक तक घटा है जबकि नीतिगत दर में 135 आधार अंकों की कमी की गई है।

## नषिकर्ष

RBI ने जनि नीतगत हस्तक्षेपों की घोषणा की उनके पीछे इसका उद्देश्य पारेषण में सुधार लाने और बैंकिंग प्रणाली को ऋण देने के लिये प्रोत्साहति करना है। परंतु इन उपायों से ऋण में सुधार होगा या नहीं यह देखना होगा। उदाहरण के लिये बाह्य मानक से बैंकों के ब्याज मार्जनि पर असर पड़ सकता है। हालाँकि घोषणा के बाद प्रतफल में कमी आई है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कलिंबी अवधि की रेपो दर कसि सीमा तक बैंकिंग तंत्र के लिये सहायक साबति होगी। ध्यातव्य है कि वर्तमान में करीब 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य की नकदी तरलता मौजूद है। ऐसे में दीर्घावधि की दरें, उच्च सरकारी उधारी और घटती घरेलू बचत के कारण एक वशिश दायरे में समित सकती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार अनवासी नविशकों के लिये वशिश प्रतभूतियों की घोषणा करके बचत में वृद्धि करने का प्रयास करेगी। इससे मुद्रा की लागत कम करने में तो सहायता मलिंगी लेकिन इससे RBI के नकदी और मुद्रा प्रबंधन के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो सकती है।

## स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rates-to-fall-despite-rbi-status-quo>

